ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **06 Nov., 2023**

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Member, CWC; Shri Salman Khurshid, Member, CWC; Shri Pramod Tiwari, MP and Smt. Ranjeet Ranjan, MP addressed the media at AICC Hdqrs, today.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको याद है शनिवार को वेणुगोपाल जी, मैंने, रमेश जी ने आपको चार-पांच बिंदुओं से अवगत करवाया था।

पहला बिंदु कि निश्चित हार की तरफ अग्रसर है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में। ये सर्वविदित है, वो उनके संज्ञान में भी है, देशभर के संज्ञान में भी है।

दूसरा, सर्विविदित चीज है कि सबसे बड़ी साझेदारी इस चुनाव में सबसे बड़ा गठबंधन और सबसे बड़ा सहयोग अगर है, तो वो राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, छत्तीसगढ़ में या भारत में, वो है बीजेपी, केन्द्र सरकार और ईडी का। ये एक विशेष गठबंधन है, उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए।

तीसरा, हमने बिंदु आपको बताया था कि ये बहुत अजीबोगरीब वाकया है कि पहला कोतवाल, जो डेढ़ साल से इंवेस्टिगेट कर रहा है, जिसने, जो मैंने आपको चौंका देने वाले आंकड़े दिए थे, लगभग 72 केस रजिस्टर किए हैं, साढ़े चार सौ लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरा मैंने आपको चार्ट दिया था- 191 लैपटॉप, मोबाइल फोन, 850 एटीएम कार्ड, इत्यादि, इत्यादि, सबको पकड़ा है।

उस पहले कोतवाल के डेढ़ साल के अथक परिश्रम को भुलाकर एक दूसरा कोतवाल चुनाव के कुछ दिन पहले आ जाता है, यानि ईडी। अब रोचक बात ये है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई, जो जांच थी, वो 30 मार्च, 2022 की है। ये तारीख मैंने आपको बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है और ईडी ने उसको विदेश में शुरू किया है, मुश्किल से 6 महीने पहले औऱ उस 6 महीने पहले शुरू करने के बाद अभी तक कुछ उसमें तेजी नहीं पकड़ी, जब तक कि चुनाव नहीं आया छत्तीसगढ़ में। अब हर चीज हो रही है, छत्तीसगढ़ के चुनाव के चार दिन पहले, तीन दिन पहले, पांच दिन पहले।

एक व्यक्ति, जो कोरियर हैं, वो बैठकर एक वक्तव्य देते हैं, जिसके विषय में हमने आपको अवगत करवाया शनिवार को। एक दूसरे व्यक्ति जो मैनेजर कह रहे थे, अभी तक अपने को, वो चुनाव के चार दिन पहले मालिक बताते हैं, अपने आप को और जो मन में आता है, वो बोल देते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये सब चीजें, राजनैतिक द्वेष, निराधार तरीके से की जा रही हैं, लेकिन जो विशेष बिंदु, जिसके लिए हमने आपको आज तकलीफ़ दी, मैं पहले उससे आपको अवगत करवा दूँ। वो बिंदु ये है कि 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से, व्यापक रूप से प्रेस कांफ्रेंस की थी, ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। यहीं की थी, इसी मंच से की थी और आपको पूरा चिट्ठा खोलकर बताया था कि ये- ये हुआ, महादेव ऐप में, किस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुई, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए- तीन महीने से ज्यादा की बात है। भूपेश बघेल ने आरोपियों की गिरफ़्तारी और केंद्र सरकार द्वारा 28 प्रतिशत टैक्स लगाकर ऑनलाइन बेटिंग को क़ानूनी दर्जा देने की बात उठाई थी।

उसके बाद केन्द्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया और किसी रूप से जो आज कह रहे हैं, वो तब से अभी तक भी नहीं कहा, यानि अगस्त के बाद भी नहीं कहा। उसके एक हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बैन की मांग भी की थी, 30 अगस्त को। 24 अगस्त को तो प्रेस वार्ता दिल्ली में थी, 30 अगस्त को बैन की मांग की थी और रायपुर में की थी। 3 नवम्बर को, चुनाव के एक हफ्ते पहले, जैसा कि हर चुनाव में आप देखते हो, होता जा रहा है, इस साझेदारी के पार्टनर ईडी ने ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री का नाम लिया। 4 तारीख को हमने प्रेस वार्ता की। अब 4 तारीख को ही हमने माननीय चुनाव आयोग से मांग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, जो मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन उसको जरा विस्तार से मैं आपको बता दूँ। बाकी सब चीजों के अलावा, राजनैतिक पक्ष, कानूनी पक्ष के अलावा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, जो पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। वो है, जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। एक समतल जमीन, जिसके बिना चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते।

अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है और इसलिए चुनाव की वो हर प्रक्रिया, जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग, 50 साल होने वाले हैं, ये एक मूल सिद्धांत है, कानून का। यानि आप अगर कुछ ऐसी

चीज करते हैं, जिससे जमीन समतल न रहे, अनईवन हो, वन साइडेड हो, लॉप साइडेड हो, तो वो सीधा अफेक्ट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर पर। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज्यादा व्यापक चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्टरीन, जो कहती है, एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है, ईडी को। जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन-प्रतिदिन, आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है, ईडी का, साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा और हर प्रकार के आरोप आते हैं और ये सब चीजें एक हफ्ते और चार दिन पहले हो रही हैं। तो इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रिजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए।

अब दुर्भाग्य की बात ये है कि 5 तारीख को हमें लिखित कंफर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानि 6 नवम्बर, 2023, सोमवार को मिलेगा साढ़े चार बजे और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं, यहाँ पर, सब तैयारी थी और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो ज़ाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं, अभी के लिए आपके पास और कई मुद्दे हैं, वो है समतल जमीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का, तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे, औऱ निर्णित करेंगे, कब- 17 तारीख को, पर क्या दो चरण के चुनाव में, एक प्रदेश में एक चरण खत्म हो जाए, वो कुछ महत्व नहीं रखता?

तो ये बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत, इसका अगर कोई औचित्य है औऱ कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी, 7 तारीख के पहले है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक और वक्तव्य आया है। देखिए, एक तो आता है, प्रेस वक्तव्य, मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में कहा है कि बीजेपी ने पहले उठाया है, इस वक्तव्य के बारे में, जिसमें, जो तत्कालीन मैनेजर था, वो आजकल अपने आप को ओनर कहकर आरोप लगा रहा है, बघेल साहब के ऊपर और उस बीजेपी के प्रेस स्टेटमेंट के बाद, ईडी का भी प्रेस स्टेटमेंट आया है। ये साझेदारी का एक और पहलू है।

मैं आपको एक और विचित्र वक्तव्य बताना चाहता हूँ, ये माननीय चंद्रशेखर जी, जो मंत्री हैं, आईटी मिनिस्ट्री के, उनका वक्तव्य है। इसमें एक और अजीबोगरीब बात ये है

कि वो कहते हैं, "However, they did not do so and no such request is made by the state government, while they have been investigating it for the last one and half years. In fact, the first and only request has been received from ED and it has been acted upon, nothing prevented Chhattisgarh government from making similar requests". ये क्या रिक्वेस्ट है, कि ऐप को शट डाउन करो।

अब आप ये बताइए, आपका विवेक ये समझाता है आपको कि केन्द्र सरकार किसी ऐप को, जिसको ईडी 6 महीने से इंवेस्टीगेट कर रही है, जिसके विषय में स्टेटमेंट्स और वक्तव्य आ रहे हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध डालने के लिए, उसको वेट करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध के लिए? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका सीधा मालूम पड़ता है।

आपने आज तक, यानि कल प्रयत्न किया है, yesterday, बैन करने का इस ऐप को केन्द्र सरकार ने। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप, हर प्रकार के आरोप। कुछ किया नहीं, उसके बाद ये वक्तव्य देते हैं आप, 5 तारीख इसकी तिथि है, जिसमें आप दोषारोपण कर रहे हैं, प्रदेश सरकार का। मैंने आपसे शनिवार को कहा था कि कस्टम्स के हमारे बॉर्डर प्रदेश सरकार देखती है, तो दे दीजिए उनको अधिकार क्षेत्र, वो देख लेगी। उस कस्टम बॉर्डर को लांघकर ये सब लोग ला रहे हैं, रुपया दुबई से और अगर प्रदेश सरकार के पास ये पावर है कि एक्सट्रैडिशन करवा ले वहां दुबई से, तो वो भी दे दीजिए, बघेल जी करके दिखा देंगे, आपको दो दिन में।

आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप हमको बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने अनुरोध नहीं किया, लिखित है ये, वक्तव्य है। ये आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, ये बताने के लिए कि हम क्यों लुप्त थे, चुप थे, विलुप्त थे, इतने महीनों से और क्यों अचानक जागे हैं, उसको कवरअप करने के लिए इस प्रकार के वाहियात वक्तव्य आप दे रहे हैं। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि ये पूरी तरह से द्वेष से भरी राजनीति का द्योतक है। अधिकतम से अधिकतम जिम्मेदारी बनती थी इसमें, चुनाव आयोग की कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे। हस्तक्षेप नहीं, प्रतिबंध लगाएं इस प्रकार के अजीबोगरीब वक्तव्यों पर। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होने देना चाहिए था। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं और अंत में ये कहते हैं कि जो चीज आप देख रहे हैं, वो हर तरह से साझेदारी इन एजेंसीज की, सरकार की, बीजेपी की दिखाती है।

श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस या कुछ बोलते हैं तो प्रेस रिलीज तो बहुत सुनी है, देखी हैं, पर दुबई में बैठकर एक मैंनेजर कंटेंट पेश करके एक वीडियो रिलीज करे और प्रेस रिलीज जारी करे, भाजपा पार्टी, ये रिश्ता क्या

कहलाता है? टाइमिंग- कल चुनाव का पहला चरण है, छत्तीसगढ़ में। आज समय मांगते हैं, कन्फर्म होता है इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद मैं बिना कोई आरोप लगाए, पर बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम आपसे नहीं मिले, तो हम अपनी बात तो प्रथम चरण के लोगों तक नहीं कह पाएंगे न? आज हम आपके पास आए होते, मिले होते, तो शायद टाइमली होता, पर आज हमें समय न देना, एक तरह से, जिसका जिक्र अभिषेक भाई कर रहे थे, कि लेवल प्लेइंग फील्ड से इंकार किया जा रहा है।

एक और बड़ी जबरदस्त बात इसमें जो है, ऐप कल बैन किया है, पर फाइल सब खुली हैं अभी। वो बैन नहीं हुई हैं। मैं इसे और क्लीयर कर दूं, कि उन्होंने ऐप तो बैन किया, ऐप की फाइल नहीं बैन की यानि आप जाइए, बटन दबाइए, खेल जारी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि तुम बोलो, फाइल तुम्हारी खुली रहेंगी। मंत्री जी, इतना तो आपको भी मालूम होगा कि आपको बैन पूरा करना।

दूसरा, आज सिर्फ महादेव नहीं बैन हुआ है, 22 ऐप बैन हुए हैं, पूरे। यानि मोदी राज में जुआ खेलना, सट्टा लगाना एक तरह से पैरलल रोजगार चल रहा था। भई, 22 बैन किए हैं आपने, कोई एक तो नहीं बैन किया है? तो इन 21 के साथ भी तो लेनदेन हो रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि अगर बैन करना है, तो इसे पूरे देश में करो। एक ऑर्डर के साथ पूरे देश में ये पिक एंड चूज किया है।

अब सोनी का प्रमोशन भी कर दिया है, बीजेपी ने। अभी तक मैनेजर थे, अब मालिक बना दिया है और बोल किसके खिलाफ रहा है, वो- एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जिसने 3-4 महीने से उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है और नतीजे के तौर पर वो दुबई भाग गया है। छत्तीसगढ़ की धरती पर वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन दुबई में जहाँ से भारत सरकार उनको ला सकती थी, कानूनन, वहाँ सुरक्षित है। तो उनकी छत्रछाया में कुछ बोलो, कुछ खेलो, कुछ करो, जायज़ है। परंतु, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, या मैं और रंजीत रंजन जी, जो वहीं से सांसद हैं दोनों औऱ आप में भी बहुत से लोग सहमत हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकतरफा काफी आगे है और वहां, मैं पिछले 7-8 दिन से वहाँ था, हर तरफ ये बात जगजाहिर है कि वहाँ बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत आगे है। हमारे दो बड़े, 'हम दो, हमारे दो', तो हम दो की दोनों मीटिंग जो हुई हैं, उनकी उपस्थिति वीडियो निकालकर देख लीजिए, वो बता रही है कि यहाँ भाजपा का कुछ भी नहीं है, गिरावट के अंतिम दौर में है। ये बात एयर में थी कि कोई संस्था आ रही है, वो कुछ करेगी, चुनाव के पहले करेगी और तीन दिन पहले आकर ईडी... जैसा अभिषेक भाई ने कहा कि अभी तो वो पुलिस कस्टडी में, यानि ईडी कस्टडी में है और उसका बयान खुद ये कर रहे हैं और नीचे एक लाइन डाल रहे हैं कि 'सब्जेक्ट टू

इंवेस्टीगेशन'। यानि इंवेस्टीगेशन के बाद उनको लगेगा कि कोई दम नहीं है इस बयान में। एडमिसिबल है कि नहीं है, तमाम बातें आएंगे, एडमिसिबल है, तो कितना एडमिसिबल है, उसने बोला है कि नहीं बोला, अभी तो उसको ये भी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है कि उसी का है कि किसका है और आप इंवेस्टीगेशन के बाद कह दें कि साहब, हमने इंवेस्टीगेशन किया, उसकी बात में दम नहीं है, तो हमारी चुनाव की तो दोनों तारीखें जा चुकी होंगी न। तो उसके पहले मोरली आप कैसे उसको लीक आउट कर सकते हैं, बताइए आप।

तो आप पहले इंवेस्टीगेट करके अपने को तो सेटिस्फाई कर लीजिए। आरोप पहले और इंवेस्टीगेशन बाद में, ये बड़ी अजीब कहानी है। थोड़ा बहुत हम सब लोग, दो जियांट्स के बीच में बैठा हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये थ्योरी किसकी समझ में आ रही है कि आरोप तो हम लगा दें, लीगल फील्ड के जो सबसे बड़े दो नाम हैं (डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और श्री सलमान खुर्शीद), आपके बीच में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आरोप पहले आप लगा दीजिए और इंवेस्टीगेशन बाद में करिए, ये इनकी बेईमानी को दर्शाता है, इनकी गलत नीयत को दर्शाता है। ये मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, मैंने सारी बात कह दी हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन ने कहा कि सारी बात मनु सिंघवी जी ने, प्रमोद जी ने कह दी हैं। मैं दो लाइन जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम रीप्रिजेंट करते हैं। ये मुख्यमंत्री की छवि को गिराने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ में ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका तेलंगाना और मिजोरम, पांचो जगह घबराई हुई है और 2024 के पहले जो रिजल्ट आने वाला है, वो उनको गिरा रहा है। उनको ग्राफ को बहुत गिरा रहा है। ये अजीब सी बात है, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो व्यक्ति भी भाजपा का निकला। जिस गाड़ी में आप पैसों की बात कर रहे हैं, वो गाड़ी भी भाजपा की निकली और ईडी, जिसको इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में ईडी का मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी हो चुका है और जो जस्ट इलेक्शन से पहले जिस तरह की हरकतें आज छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के बेटे के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ये पूरे लोग देख रहे हैं और जैसा एक प्वाइंट जो मेरे कुलीग हैं, प्रमोद जी ने रेज किया है, वो एक बार फिर, जो मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि आप ऐप को प्रतिबंध करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डॉट-एपीके फाइल है, वो लगातार सट्टे का खेल खिला रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट है और हम लोग यही कहेंगे कि ये सारा खेल, जो उनकी हार है, उसको दर्शाता है और अनफॉर्चुनेट है।

जो चुनाव आयोग होता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम लोग उनसे मिलकर शिकायत करना चाहते थे और उससे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस तरह एक प्रेस रिलीज ईडी करता है और वीडियो एक पार्टी की तरफ से, यानि भाजपा की तरफ से रिलीज होती है, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? ये बात छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री और हम लोग आज आपके माध्यम से चुनाव आयोग से बार-बार कह रहे हैं, जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि क्या आप 8-9 को समय देंगे, तो पहला चरण समाप्त होने के बाद करेंगे, तो अभी तो हम कह रहे हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, तो चुनाव के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं।

एक अन्य प्रश्न पर कि क्या आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने आपको समय देकर उसको कैंसिल किया, ड़ॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, जो हमको कहना था, चुनाव आयोग के बारे में हमने बड़ा स्पष्ट कहा है, बाकी शब्द तो आपके हैं। हम ये बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि ये बड़ा लॉजिकल, बड़ा सरल मुद्दा है कि अगर आरोप हमारा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विरुद्ध है, ईडी के विरुद्ध है औऱ चुनाव कल है और आपने समय दिया है, तो समय कैंसिल करके उसको 8 या 9 कहने का, कम से कम पहले चरण से तो कोई संबंध नहीं रखता। आप या तो एक्शन लेकर दिखा देते, हमसे नहीं मिलने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। या तो आप इसको प्रतिबंधित कर देते, लेकिन यदि आप मिलेंगे, हमको 8-9 को तो उसका औचित्य तो बहुत ही शून्य हो जाता है, जहाँ तक पहले चरण का सवाल है। ये तो बहुत सरल बात है।

एक अन्य प्रश्न पर कि क्या पहले कभी चुनाव आयोग ने समय देकर मिलने से मना किया है, क्या ये अभूतपूर्व नहीं है? डॉ. सिंघवी ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसी बहुत सारी याचिकाएं हमने देखी हैं, 2019 में हमने देखी हैं, उसके बाद देखी हैं, और बहुत हद तक जो आप कह रहे हैं, वह सही है। ऐसा करीब-करीब पहले कभी नहीं हुआ। उसको निरस्त करें, मानें- न मानें, एक्शन लें- न लें, वो अलग मुद्दा है। कई बार निरस्त चीजों को लेकर हम कोर्ट गए और हमने कोर्ट से वापस आदेश लिया और वापस गए, लेकिन कुछ सुनना नहीं, उसके लिए फोरम नहीं देना, निर्णय़ नहीं देना, ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है।

केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के बयान को लेकर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये मुद्दे थे, तो दुबई, हवाला ऑपरेटर, रुपया आ रहा है बाहर से, कोरियर का वक्तव्य परसों और कल, इस सोनी

व्यक्ति का ये पांचों चीजें चुनाव के एक हफ्ता पहले क्यों हो रही हैं, यही प्रश्न मैंने आपसे शनिवार को भी पूछा था। स्मृति जी इसका उत्तर क्यों नहीं देती?

उस हवाला ऑपरेटर या उस व्यक्ति जिसको खुद ईडी मान रही है कि 6-8 महीने से इंवेस्टीगेट कर रही है, उस पर रोकथाम लगाना, उसको लाना, उसके ऊपर प्रोसीक्यूशन करना, कोई भी वक्तव्य तो पहले करना था, क्यों नहीं किया गया? डेढ़ साल पहले जबकि ये एफआईआर है स्टेट गवर्मेंट की मार्च 22 को, उसके बाद इतने अरेस्ट हुए हैं, तो उसके बाद से अब क्या औचित्य है, स्मृति जी का इस बात को कहने का और उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमने इसलिए नहीं किया, बैन कि आपने, यानि छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुरोध नहीं किया इसके बारे में। ये भी खैर फैक्चुअली गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मौखिक रूप से मांगा है, लेकिन उसको छोड़िए आप। क्या हमारे अनुरोध के आधार पर चलते हैं, आप? हमारे तो बहुत सारे अनुरोध पैंडिंग हैं, आपके पास।

इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर डॉ. सिंघवी ने कहा कि अमित शाह जी को पता है कि इन प्रदेशों में वो बुरी तरह से हार रहे हैं। ये कुछ इससे गठबंधन हो जाए, उससे गठबंधन हो जाए, उससे गठबंधन हो जाए, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, अब निश्चित हार है।

एक प्रश्न पर कि जिसके बारे में लगातार आप कह रहे हैं कि दुबई से एक व्यक्ति है, वहाँ से वीडियो जारी किया है, वो मैनेजर था, हालांकि बीजेपी कह रही है, कि वो मालिक है, लेकिन जो 508 करोड़ देने की बात आ रही है, उस पर क्या कहना है? डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो वही चीज है जो मैंने आपको शनिवार को बताई, ये तो वही प्रश्न है और अभी पिछला प्रश्न है, उसका उत्तर यही है। इस 508 या 38 करोड़ का एक पैसे का इन्होंने कोई भी मनी ट्रेल एस्टेब्लिश किया है कि नहीं, सिवाए चुनाव के चार दिन पहले दो लोगों के वक्तव्य पर। बघेल जी ने कहा था कि किसी कोरियर से आप कुछ कहलवा लें, तीन दिन पहले, तो क्या वो प्रमाणित हो जाता है? इस व्यक्ति को जो अब अपने आपको मालिक कह रहा है आपने बैन तक नहीं किया कल तक और उसके बाद आपने कोई एक्शन नहीं लिया, एक एक्सट्रैडिशन नहीं किया, क्यों नहीं किया? पूरी केंद्र सरकार आपकी है, कस्टम आपके पास है, एक्सट्रैडिशन आपके पास है, विदेश से बात करना आपके पास है, तो वही उत्तर हुआ। ये सिर्फ कह देने से क्या होता है? आपके सामने क्या तथ्य दिया गया है? आज भी, कोई तथ्य नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि क्या नहीं किया, डेढ़ साल में शुरुआत किसने की, हमने। 450 लोगों को अरेस्ट किसने किया, चंद्रशेखर जी की सरकार ने

किया? 49 केस फाइल हुए, किसने किए, सभी डिस्ट्रिक्ट दिए मैंने आपको, राजनंद गांव, दुर्ग, सब तो दे दिए मैंने आपको शनिवार। इतने सारे मोबाइल फोन जब्त हुए, इतने सारे लैपटॉप, क्या सब चंद्रशेखर जी की सरकार ने किया? ये तो कल से सिर्फ हल्ला कर रहे हैं एक-दो हफ्ते से चुनाव की वजह से। ये राजनीतिक ईडी है।

On a question that what do you have to say on Minister's claim that the Chief Minister has not written to the ED directly, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- But it's not necessary. I have just answered this under which law, which system does ED ever wait for a Chief Minister to write? I wish it was waiting for anybody. They selectively proceed wherever they want, they don't want, for anybody. Please let them say that in future, the SOP says- there unless the Chief Minister invites, we will not proceed. That is only a Section 6 requirement of the CBI. वो सीबीआई भी वायलेट कर रही है, ईडी का सवाल कहाँ से उठता है।

On another question that what is the next step of Congress Party regarding this, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- It is definitely an attempt to obstruct a free and fair election. It is definitely an attempt to muddy the field because the BJP knows they are losing badly. It is definitely an attempt to paint a black picture where they know that the 'Janta' realise the achievement of the Congress Government. As far as the other larger issue is concerned on the same issues, there are several matters from Chhattisgarh, many of which I am appearing in, where bail has been guaranteed and officers are harassed. Till today, the names, I gave you on Saturday not a single officer, not one- single has been found to be culpable in any charge sheet with any detail. Many have got bailed the matters are again being heard on 22nd November 2023 by the Supreme Court. Your larger question about Lok Sabha elections will be discussed later is not the time to answer it.

On another question, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Future course of action is the same to make sure that we educate the public and the nation through you, first and foremost and then keep trying, keep going to constitutional authorities, keep putting a point of view whether they hear or not. It's their job.

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC